International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

2047 तक भारत को विकसित बनाने के लिए भारत का रास्ता

डॉ. अजय कुमार

एसोसिएट प्रोफ़ेसर, राजनीतिक विज्ञान विभाग, गुरुनानक खालसा कॉलेज, करनाल।

भारत 2047 में अपनी आजादी के सौ वर्ष पूरे कर आजादी की एक नई सदी में प्रवेश करेगा और निश्चित रूप से प्रत्येक जागरूक भारतीय के लिए ये एक विचारणीय विषय है कि आजादी की नई सदी का भारत कैसा होगा? एक अच्छे भारत की परिकल्पना प्रत्येक भारतीय कर सकता है और उस अच्छे को प्राप्त करने के लिए सभी भारतीय सौ वर्ष का एक लम्बा सफर तय कर रहे हैं। इस बात का विश्लेषण करना जरूरी होगा कि 1947 में जो समस्याएँ भारत के लिए भयावह थी, क्या वो 2047 तक मिट चुकी होंगी? तथा भारत के विकास के मार्ग की बाधाएँ हमारे नियंत्रण में आ चुकी होंगी तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जरूरी सुविधाएँ सभी को मिल चुकी होंगी। कया हम वाकई में पूर्ण विकसित राष्ट्र बन चुके होंगे और अगर हमारी परिकल्पना ये कहती है कि 'हाँ' तो ये समझना जरूरी होगा कि वर्तमान वैश्विक और घरेलू परिस्थितियों को देखते हुए ये मंजिल किन रास्तों पर चल कर प्राप्त की जा सकेगी और हमारी इस 'विकसित भारत रूपी मंजिल' का स्वरूप कैसा होगा? इन सब पहलुओ के साथ–साथ भारतीय इतिहास, संस्कृति, भौगोलिक स्थिति और आध्यात्मिक समझ को भी महत्त्व देना जरूरी है। एक स्थाई व आदर्श विकसित राष्ट्र का उद्देश्य जो हमें प्राप्त करना है उसके लिए विस्तृत रूप से क्या–क्या किया जाना जरूरी है उन सभी विषयों का विश्लेषणात्मक अध्ययन इस शोध पत्र में किया जा रहा है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब 1947 में भारत आजाद हुआ उस समय लाखों निर्दोश लोग अत्याचारपूर्ण मौत और करोड़ों लोग बेबसी में पलायन के शिकार हुए। ये ठीक है कि उस समय के ज्यादातर देश परतंत्र और अत्यंत पिछड़े थे और भारत भी भौतिक रूप से तो पिछड़ा था ही साथ ही समकालीन सामाजिक धार्मिक परिस्थितियों ने यहाँ बेहद नफरती वातावरण बना दिया था और इस वातावरण को हम पूरी तरह से आज भी नहीं सुधार पाए। इसलिए जरूरी है कि हमारा 2047 का भारत एक विकसित, भौतिक सम्प्रभु राज्य के साथ–साथ अध्यात्मिक व संगठित भारतीय राष्ट्र भी होना चाहिए। एक भौतिक रूप से विकसित राज्य के लिए जहाँ हमें आधारभूत भौतिक संरचनाओं का विकास करना है वहीं अध्यात्मिक और संगठित विकसित राष्ट्र के लिए हमें भारतीय संस्कृति के शाश्वत् और सहबद्ध करने वाले मूल्यों को ढूँढ़ना होगा तथा इन दोनों पक्षों के साथ–साथ ये भी ध्यान देना होगा कि 2047 का विकसित भारत सिर्फ उस समकाल के लिए ही नहीं होगा बल्कि एक स्थाई विकसित देश होगा जिसका स्वरूप पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श विकास का पैमाना बन सके। अगर हम भौतिक विकास की बात करें तो भारत में उद्योगिकरण की गति को तीव्र किया जाना अत्यंत जरूरी है क्योंकि हम पहले ही यूरोप के उद्योगिकरण से काफी ज्यादा पीछे हैं, यहाँ तक कि हमारे बाद एक नई राजनीतिक व्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ साम्यवादी राष्ट्र चीन भी पिछले

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

45 वर्ष में अत्यंत तीव्र गति से औद्योगिक विकास के पथ पर हमसे काफी आगे निकल चुका है। हालाँकि वर्तमान कुछ नीतियाँ भारतीय घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दे रही हैं लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास की गति मे हम अभी भी बहुत पीछे हैं। भारत में औधोगिक विकास के लिए जरूरी है कि वैज्ञानिक खोज व आविष्कार की गति को बढ़ाया जाए। इसके लिए विभिन्न स्तर पर योजनाएँ बनाई जाएं और युवाओं को उत्साहित करने के साथ–साथ आज के बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा कुछ नये आविश्कार करने की भावना विकसित की जाए। शिक्षा में शोध को विशेष महत्त्व देकर नई पीढ़ी के मस्तिष्क का वैज्ञानिक विकास में अधिक से अधिक उपयोग किया जाना जरूरी है। लेकिन ये भी ध्यान देना जरूरी है कि विज्ञान विकास के लिए हो विनाश के लिए नहीं। हमने भारतीय सांस्कृतिक इतिहास में पढ़ा है कि 'महाभारत' के युद्ध में विज्ञान का इतना ज्यादा प्रयोग हुआ कि वो एक भयंकर विनाश में बदल गया। इसलिए विज्ञान पूर्ण रूप से विवेकसंगत मानवीय नियंत्रण में होना चाहिए। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटैलिजैंसी पर बड़ा बल दिया जा रहा है। इस प्रकार के विकास का प्रयोग सोच समझकर होना चाहिए। विज्ञान के प्रत्येक स्वरूप का प्रयोग मानवीय हित में ही होना चाहिए। हमें निश्चित रूप से ये मान लेना चाहिए कि विज्ञान को मनुश्य ने मानवीय भलाई के साधन के रूप में बनाया है इसलिए ये हमेशा ध्यान दिया जाए कि वो एक साधन ही रहे। इतना समझ लेना अत्यंत जरूरी है कि विज्ञान अगर बहुत अधिक गुणवत्ता रखता है किसी प्रकार कि कोई गलती की गुजांइश नहीं छोड़ता तो भी वो मनुष्य का स्थान नहीं ले सकता क्योंकि निर्मित कभी भी निर्माता से ऊपर नहीं हो सकता। प्रत्येक निर्मित अवयव निर्माता की सुविधा के लिए ही है इसलिए उसे कभी भी निर्माता से ऊपर नहीं रखा जाना चाहिए। किसी मशीन से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है लेकिन मनुश्यों को बेरोजगार करके अगर कुछ व्यक्तियों को अधिक अमीर और बाकी को दयनीय स्थिति में पहुँचा दिया जाए तो ये विज्ञान का मानव सभ्यता के अहित में इस्तेमाल करना होगा। हालाँकि ये सही है कि वैज्ञानिक भाोधों के माध्यम से उन्नत तकनीकी ज्ञान और आधुनिक मशीनीकरण का लाभ उठाकर उत्पादन को बढ़ाया जाए और लोगों के जीवन को अधिक सुविधापूर्ण बढ़ाया जाए। विज्ञान की सहायता से आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जाए। आज भारत वि व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। लेकिन ये अभी भी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से बहुत पीछे है। भारत अपने पड़ोसी देश चीन से आर्थिक रूप से काफी पीछे है जबकि चीन की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था भारत की स्वतंत्रता के बाद अस्तित्व में आई। हमें अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत इस ढंग से करनी चाहिए कि भारत जहाँ एक तरफ पूँजीवादी भाक्तियों के समकक्ष खड़ा हो सके वहीं दूसरी तरफ अपने समाजवादी व कल्याणकारी मूल्यों को भी ना भूले। बड़े उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना जरूरी है ताकि उच्च गुणवत्ता पूर्ण और अधिक मात्रा में उत्पादन करके निपति को बढ़ावा दिया जा सके लेकिन साथ–साथ कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देकर तथा लोगों के मन में स्थानीय स्तर पर उत्पादित की गई वस्तुओं के प्रति आकर्षण पैदा करके निजी माँगों को घरेलू उत्पादन से ही पूरा किया जाए ताकि हमारा आयात घट

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

सके। आज भारत ज्यादातर बड़ी आर्थिक भाक्तियों के साथ व्यापार घाटा उठा रहा है। इस व्यापार घाटे को कम करना अत्यंत जरूरी है। भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भारत को आर्थिक शक्ति बनाने के साथ–साथ भारतीयों की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बनाना बहुत जरूरी है अर्थात् भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय वास्तव में बढ़नी चाहिए। जब प्रति व्यक्ति आय की बात होती है तो देश के सभी लोगों की आय का औसत निकाल लेना वास्तविकता से दूर ले जाता है। इसलिए प्रति व्यक्ति आय का जो औसत सामने आता है उसके स्थान पर ये ध्यान दिया जाए कि न्यूनतम आय प्रस्तावित औसत आय से कम न हो फिर वास्तविक औसत आय नियमित रूप से प्रस्तावित औसत आय से ज्यादा निकल जाएगी। भारत की आर्थिक मजबूती में भारतीयों की न्यूनतम आय को उच्च स्तर पर ले जाकर न सिर्फ भारत से गरीबी का उन्मूलन किया जा सकेगा बल्कि भारतीयों का जीवन स्तर भी उच्च किया जा सकेगा और भारत के अन्दर होने वाले प्रत्येक प्रकार के व्यवसाय को गति प्रदान की जा सकेगी। किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था का सबसे सुदृढ़ पक्ष वहाँ के लोगों की मूलभूत भौतिक जरूरतों को स्थाई रूप से पूरा करना होता है। इसलिए विकास इस रूप में होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को भोजन, आवास, वस्त्र, चिकित्सकीय सुविधाएँ पर्याप्त रूप से मिल सकें और ये सब गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए ताकि प्रत्येक भारतीय एक स्वस्थ जीवन व लम्बी जिन्दगी को सम्मानपूर्ण ढंग से जी सके। प्रत्येक व्यक्ति को माँ की कोख से ही पौश्टिक आहार मिलना जरूरी है ताकि भारतीयों में भाारीरिक विकार न रहें और ये पौश्टिक आहार उसे पूरी उम्र मिलना चाहिए ताकि प्रत्येक भारतीय न सिर्फ अपने अच्छे स्वास्थ्य का स्वयं आनन्द ले बल्कि चिकित्सकीय सुविधाओं पर खर्च किये जाने वाले पैसे को भी दूसरे क्षेत्रों में लगाया जा सके और राष्ट्र हित में प्रत्येक भारतीय उम्र के आखिरी पड़ाव तक स्वस्थ शरीर के साथ योगदान देता रहे। भारत में मातृ–शिशु मृत्यु दर को लगातार कम किया जा रहा है। इसे 2047 तक विश्व स्तर पर सबसे अच्छी स्थिति में पहुँचाना होगा। वर्तमान में भारत जीवन प्रत्याज्ञा और जीवन स्तर में काफी नीचे स्थान रखता है। इसे उच्च स्तर तक लाना होगा। जीवन स्तर के उच्च स्तर पर लाने के साथ–साथ ये भी जरूरी है कि भारतीय प्रशासनिक जीवन में फैली व्याप्त बुराईयों को भी दूर करना होगा। आज यहाँ प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर विभिन्न स्वरूपों में फैला भ्रष्टाचार न सिर्फ एक प्रशासनिक बुराई है बल्कि मानवीय सोच में भी कई प्रकार के विकारों को जन्म देता है। कई प्रकार के अलगाववादी विचार प्रशासनिक भ्रष्टाचार के कारण भी पैदा होते हैं। 1947 में भारत की आज़ादी के समय से अब तक के सफर में प्रशासनिक भ्रष्टाचार लगातार बड़ा है हालाँकि आर.टी.आई. जैसे कानून के रूप में कुछ सुधारात्मक प्रयास जरूर किये गए हैं लेकिन अभी काफी कुछ और प्रयास भी किये जाने जरूरी हैं। अगर प्रत्येक व्यक्ति को खुद से भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई कानून बनाया जा सके तो इससे न सिर्फ भ्रष्टाचार रुक पाएगा साथ–साथ लोगों में भाासन के विरुद्ध असंतोष भी कम होगा और कई प्रकार के अलगाववाद पर विराम लगेगा। अगर कोई ऐसा कानून बनता है

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

जिसमें पीड़ित व्यक्ति तथ्यों के साथ सारी जानकारी सरकार द्वारा बनाई गई विशेष साइट पर डालें और उस साइट पर सारा ब्यौरा पहले से ही अपलोड हो इस स्थिति में दोनों का डाटा मैच होने पर भ्रश्ट अधिकारी के विरुद्ध उस साइट से स्वतः ही आदेश जारी हो जाए। ये भ्रष्टाचार सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि भाई भतीजावाद, जातिवाद, नारी सम्मान और भी अन्य कई रूपों में देखा जाता रहा है। भ्रश्टाचार की समाप्ति के साथ–साथ राष्ट्रीय नेतृत्व का चरित्र भी उच्च कोटि का होना जरूरी है। ये स्पष्ट है कि नौकर ाही कार्यपालिका का स्थाई भाग है जो अस्थाई भाग या राजनीतिक कार्यपालिका यानि मंत्रिमण्डल के अधीन कार्य करता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये मंत्रिमण्डल जितना जिम्मेदार, जबावदेह, निश्पक्ष, कार्यशील, गुणवत्तापूर्ण, कुशल, दूरदर्शी, पारदर्शी, राष्ट्रभक्त, दृढ़विश्वासी, साहसी, मर्यादित, निर्भयी, निस्वार्थी और यथासंभव ज्ञानी होगा, कोई भी देश उतनी ही अधिक तरक्की करेगा। इस प्रकार का नेतृत्व प्राप्त करने के लिए कुछ राजनीतिक दिशा निर्देश भी तय होने चाहिएं। राजनीति में भाग लेने वालों के लिए भी कुछ योग्यता निश्चित होनी चाहिए और गलत जानकारी देने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। प्राचीन राजनीतिक दार्शनिक 'प्लेटो' ने कहा था कि राजा सर्वोच्च गुणों को धारण करने वाला होना चाहिए अगर नेतृत्व सही होगा तो वो देश की मानवीय भाक्ति और भौतिक संसाधनों का भी उचित प्रयोग कर पाएगा। जहाँ योग्यता को महत्त्व दिया जाता है वहाँ विकास होना तय है। महान राजनीतिक वैज्ञानिक 'अरस्तू' ने कहा न्याय का योग्यता पूर्ण वितरण किया जाना चाहिए। आधुनिक राजनीतिक आर्थिक विद्वान जॉन रॉल्स भी न्याय के वितरणात्मक विचारों के माध्यम से जहाँ एक तरफ योग्यता को महत्त्व देते वहीं दूसरी तरफ कमजोर वर्ग के हितों का भी विशेश ध्यान रखते हैं। भारत की आरक्षण व्यवस्था पहले से ही सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक न्याय को तथा सामाजिक आर्थिक सुरक्षा को स्थापित करने का प्रयास कर ही रही है लेकिन इसके साथ–साथ योग्यता को भी विशेश सम्मान दिया जाना बहुत जरूरी है। भारतीय संविधान जहाँ नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से सामाजिक न्याय और कल्याणकारी राज्य की तरफ भारत को आगे बढ़ा रहा है वहीं दूसरी तरफ मौतिक अधिकार योग्यता व स्वतंत्रता को बढ़ावा देने वाले हैं लेकिन संविधान के लागू होने के 75 वर्ष बाद भी बहुत से मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत सच्चे अर्थों में लोगों तक नहीं पहुँच पाए हैं। भारतीय संविधान में दिए गए विस्तृत उपबन्धों को सही ढंग से अगर लागू किया जाए तो 2047 तक हम काफी आगे बढ़ चुके होंगे। भारतीय संविधान हमारी विदेश नीति के लिए भी दिशा निर्देश देता है जो भारत जैसे सहिश्णु और 'सर्वे भवन्तु सुखिना' में वि वास रखने वाले देश के लिए अत्यंत उचित नजर आते हैं। लेकिन मूल्यात्मक ढंग से ये उचित है परंतु व्यवहारवादी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उचित सम्मान पाने के लिए भारत को अपनी सैन्य भाक्ति को अत्यंत मजबूत करना होगा। वर्तमान में भारत अपने पड़ोसी देश चीन से भी काफी पीछे है जबकि वि व भाक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के बराबर पहुँचने के लिए बहुत ज्यादा प्रयासों की जरूरत है। हालाँकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि शक्ति कभी भी स्थिर नहीं रहती समय,

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

स्थान और परिस्थितियों के साथ ये बदलती रहती हैं। आज चीन भारत से आगे है जबकि इतिहास गवाह है कि चीन को भारत ने कई बार मात दी थी। भारत की मजबूती के लिए अत्यंत जरूरी ये भी है कि सारे भारत में पारम्परिक समझ पैदा करने के लिए साँझी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा दिया जाए और साँझी भाषा का भी विकास किया जाए। अगर भारत 2047 तक कोई एक ऐसी भाषा का विकास कर लेता है जिसमें लगभग सभी भारतीय भाशाओं का समावेश हो और जो पूरे देश में लागू की जाए तो ये बहुत लाभकारी सिद्ध होगी। भाषई समरूपता लाने के साथ–साथ भौगोलिक समरूपता के लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए। ये ठीक है कि हिमालय और हिन्द महासागर एक दूसरे का स्थान नहीं ले सकते लेकिन हिमालय और हिन्द महासागर से मिलने वाले लाभ का समान उपयोग सारा देश कर सके तथा उनसे उत्पन्न होने वाली समस्याओं को भी सारा देश समान रूप से बाँट ले इस प्रकार की नीतियाँ तैयार की जानी चाहिएं। पीछे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार नदियों को जोड़ने की योजना लाई थी इस प्रकार की योजनाएँ अत्यंत जरूरी हैं। वर्तमान में भारतमाला कार्यक्रम के द्वारा सारे देश को जोड़ने का प्रयास किया भी जा रहा है। अगर भारत भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से एकरूप होगा तो ये बात हमारी प्रभुसत्ता को भी मजबूती देगी। लगातार सरकार इस तरफ प्रयास भी करती रही है कि भारत अपनी बन्दरगाहों को आधुनिक सुविधा सम्पन्न करने के साथ सुरक्षित बनाने का प्रयास भी लगातार कर रहा है। ये जरूरी भी है कि 2047 तक भारत की सामुद्रिक सीमाएँ और स्थलीय सीमाओं की सुरक्षा के साथ वहाँ तक सभी भारतीयों की पहुँच हो चुकी हो ताकि हमें पता चल सके कि हमारा भारत कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है और हम उसकी सुरक्षा और उसके साथ अपनेपन का विचार विकसित कर सकें। हालांकि सामान्य जानकारी के आधार पर ये सब कुछ हो रहा है लेकिन ये भी जरूरी है कि सभी भारतीयों को प्रत्यक्ष रूप से भी सारे भारत को घूमने का मौका मिले। सरकार इसके लिए योजना तो बना भी रही है परंतु उनका लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाना होगा। भारत की अपनी यातायात व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त करना होगा फिर चाहे वो रेलवे हो, सड़क हो, नौका परिवहन या जलमार्गों का विकास हो और चाहे हवाई मार्ग को आधुनिक ढंग से समय की माँग के अनुरूप विकसित करना हो। भारत की कुछ समस्याएँ प्रकृति की दी हुई हैं उन्हें स्थाई रूप से हल करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन हमें चाहिए कि 2047 तक उन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त किया जा सके। 2002 को गुजरात में भुज के भूकम्प के बाद बड़ी तीव्र गति से पुर्नजीवन शुरु किया गया और लोगों के जख्मों पर न सिर्फ मरहम लगी बल्कि उन्हें बाद के अच्छे जीवन का अनुभव भी हुआ परंतु जो बुरे अनुभव भूकम्प देकर गया उन्हें वो कभी नहीं भूल सकते। इसी प्रकार 2004 की सूनामी की घटना में लाखों लोग मारे गए। इसी प्रकार केरल में आई प्राकृतिक आपदा अत्यंत भयावह थी। उत्तराखंड का जल प्रलय अत्यंत विकराल था। इसी प्रकार 2019–21 में चली कोरोना की महामारी ने भी बड़ा व्यापक नुक्सान किया। हालांकि कोरोना के बारे में ऐसा भी माना जाता है कि ये किसी मानवीय गलती का परिणाम हो सकता है जो

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

किसी देश के वैज्ञानिकों की प्रयोगशाला से निकलकर दुनिया भर में फैली या फैलाई गई। इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएँ न सिर्फ जनता का मनोबल तोड़ती हैं और साधारण जीवन को बुरी तरह प्रभावित करती हैं बल्कि विकास की गति को भी बड़े स्तर पर बाधित करने के साथ–साथ भविष्य के जीवन के लिए अवि वास पैदा करती हैं। इसलिए ये जरूरी है कि जहाँ तक संभव हो सके प्रत्येक वर्श आने वाली बाढ़ों को रोकने के लिए नदियों के पानी का उचित वितरण व बाँधों को अत्यंत सुरक्षित करने की व्यवस्था की जाए। भूकम्पों की लगातार होने वाली घटनाओं को ध्यान में रखते हुए दक्षिण भारत के भूकम्प रोधी क्षेत्र में विशेष आवासीय और औधोगिक क्षेत्र विकसित किए जाएं जबकि उत्तरी भारत में कृषि सम्बन्धित क्षेत्रों को अधिक विकसित किया जाए। मकानों को भूकम्प रोधी या अत्यंत मजबूत बनाने के लिए लोगों को मानसिक रूप से तैयार करने के लिए वातावरण बनाया जाए। कुल मिलाकर प्राकृतिक आपदाओं पर नियंत्रण पाने के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित किया जाए। हमें अपने समुद्र, पर्वत, नदियों, वन्य क्षेत्र और वन्य व पालतू जीवों के साथ अपनेपन का अनुभव करते हुए उन सबके प्रति सजीवता व प्रेम का विचार रखना होगा। हमें सभी प्राकृतिक संरचनाओं के प्रति न्याय भाव रखते हुए उनके साथ प्राकृतिक न्याय करना होगा। अगर एक नदी के क्षेत्र में इमारतीय या सड़कीय जैसी संरचनाएँ विकसित की जाती हैं तो वो प्रकृति के साथ अन्याय है और फिर कभी भी प्रकृति उस क्षेत्र में विनाश ला सकती है इसलिए प्रकृति के जो क्षेत्र जिस उद्देश्य से प्रकृति ने बनाए हैं उनकी समझ रखते हुए दूरदर्शी सोच के साथ सरंचनाएँ विकसित की जाएं। मनुष्य भी प्रकृति का बनाया एक अनमोल जीव है तो उसके साथ भी न्याय करना अत्यंत जरूरी है। हमें पूरी मानव जाति के साथ न्याय भाव रखने के साथ–साथ भारत के प्रत्येक वर्ग के लिए न्याय प्रदान करना होगा। हमें भारत के जवानों, किसानों, व्यापारियों, नौकरीपेशा लोगों, कामागारों, व्यावसायिकों आदि सभी के लिए सुगम और सही न्याय की व्यवस्था करनी होगी। भारत की स्वतंत्र और निश्पक्ष न्यायपालिका की तटस्थता को बनाए रखने के साथ–साथ उसमें तीव्रता और कुछ मानवीय मूल्यों के संदर्भ में सकारात्मकतापूर्ण मूल्यपरकता को भी भाामिल करना होगा। ये ध्यान रखना चाहिए कि भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका भारत की राश्ट्रीय एकता का एक अति महत्त्वपूर्ण संवैधानिक माध्यम भी है इसलिए अगर हमारी न्याय व्यवस्था सही होगी तो राष्ट्रीय एकता भी मजबूत होगी और सामाजिक विकास को भी बल मिलेगा। कई बार उचित न्याय न मिलने पर व्यक्ति समाज और राश्ट्र के विरुद्ध विचार रखना भाुरु कर देता है। इस प्रकार के नकारात्मक पहलू को दूर करना होगा और 2047 तक सभी के अन्दर न्याय के प्रति पूर्ण विश्वास पैदा करना होगा। हमें उन ऐतिहासिक भूलों को सुधारना होगा जो भारत के विभाजन का कारण रहीं। 2047 में जब हम 1947 से सौ वर्श आगे होंगे तो निश्चित रूप से हमारे पास ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ हमें फिर से 1947 जैसे हालात न देखने पड़ें। ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत विविधताओं वाला देश है और इसमें स्थाई एकता बनाई जाए इसके लिए लगातार प्रयास होने के साथ–साथ कोई स्थाई समाधान भी जरूरी है। इसके लिए भारत

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

की सामाजिक–धार्मिक व्यवस्था में एकता के भाव पैदा करने के लिए विवाह व्यवस्था में कुछ विकसित मूल्य जोड़े जा सकते हैं। अर्न्तजातीय, अर्न्तधार्मिक, अर्न्तक्षेत्रीय विवाहों को बढ़ावा दिया जाए लेकिन साथ में पारिवारिक मूल्यों को कम न होने दिया जाए। पारिवारिक मूल्यों व अर्न्तसंस्कृतियों में विवाह को बढ़ावा देने वाले विचारों को जन–जन तक पहुँचाया जाए तथा सरकार के द्वारा विशष सुविधाएँ भी दी जाएं। पारिवारिक मूल्यों को राष्ट्रीय एकता के अनुरूप विकसित करने के लिए योजनाएँ बनाई जानी चाहिएं। जैसा कि ये कहा जाता है कि परिवार पहली पाठशाला है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए 'परिवार–पारिवारिक मूल्य व राश्ट्रीय एकता' जैसे कोई कार्यक्रम चलाएँ जाने चाहिएं।

भारत में सामाजिक एकता के मूल्यों को स्थापित करना इसलिए भी बहुत जरूरी है कि 2047 तक सिर्फ 'भारतीय सम्प्रभु राज्य' को ही नहीं बल्कि भारतीय राष्ट्र को भी पूर्ण विकसित देखना चाहते हैं। भारत में रहने वाले प्रत्येक अल्पसंख्यक को चाहे वो क्षेत्रीय, धार्मिक या जातिगत अल्पसंख्यक हो मुख्यधारा में साथ लेकर चलना होगा। राजनीतिक जागरूकता के साथ–साथ राजनीतिक सहभागिता को भी पूर्ण रूप से विकसित करना होगा। भारतीय समाज का कोई भी वर्ग अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी से या यूँ कहें अपने राजनीतिक योगदान से वंचित नहीं रहना चाहिए। भारत में एक ऐसी राजनीतिक संस्कृति का विकास किया जाए जिसमें प्रजातंत्र के होते हुए भी जिनकी संख्या कम है उनकी राजनीतिक सहभागिता ज्यादा हो सके। जैसे आरक्षण की व्यवस्था के द्वारा सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आगे आने का मौका मिला है उसी प्रकार जातिगत रूप से कम संख्या रखने वालों की राजनीतिक भागेदारी इतनी बढ़ा दी जाए कि वो अपने आप को अल्पसंख्यक ही न मान पाएं। भारत की एकता के लिए ये अत्यंत जरूरी है कि यहाँ के लोगों में उपेक्षिता का भाव न रहे। जिन लोगों की संख्या ज्यादा है वो तो वैसे ही अपना स्थान प्राप्त कर लेते हैं लेकिन कम संख्या वालों की उच्च राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित कर उनमें वि वास बढ़ाया जा सकता है। भारत में राजनीतिक संस्कृति को दूरदर्शितापूर्ण रूप से मजबूत करना होगा। जहाँ एक तरफ सर्वमान्य राजनीतिक मूल्यों जैसी स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार आदि को सभी के लिए उपलब्ध कराना है वहीं भारतीय परिस्थितियों के संदर्भ में विशेष राजनीतिक मूल्य जातिगत सहभागिता को भी महत्त्व देना होगा। भारत में जाति व्यवस्था यहाँ के नागरिक जीवन का बहुत बड़ा पक्ष है और इसके लिए जरूरी है कि जहाँ एक तरफ जातिवाद को कमजोर करने के प्रयास किए जाएं वहीं दूसरी तरफ जब तक ये कमजोर नहीं पड़ती तब तक सभी जातियों में वि वास पैदा करने के लिए उनकी सहभागिता भी सुनिश्चित की जाती रहे और जैसा कि ऊपर कहा गया है जिसकी जितनी कम संख्या उसके प्रति उतना ही ज्यादा संवेदनशील होकर उसे विशेष राहत प्रदान की जाए। इस सबके लिए हमें सभी भारतीयों में एक ऐसी सोच विकसित करनी होगी जो उच्च सामाजिक नैतिकता से परिपूर्ण हो अर्थात् पूरे समाज की एक सावयव अर्थात् शरीर मानना होगा और इस सोच को विकसित करने के लिए हम अपनी शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक धार्मिक

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

संस्थाएँ व मीडिया के विभिन्न माध्यमों आदि का सहारा ले सकते हैं। भारत की शिक्षा व्यवस्था जहाँ एक तरफ व्यक्ति की जीवन याचिका उपलब्ध करने वाली हो वहीं दूसरी तरफ उसके व्यक्तित्व तथा सामाजिक बोध को भी विकसित करने वाली होनी चाहिए। अगर भारत में समाज के सावयवी सिद्धांत को विकसित किया जाएगा तो ये एक अत्यंत विवेकपूर्ण मार्ग होगा जिस पर चलकर न सिर्फ सामाजिक एकता को पाया जा सकेगा बल्कि समाज के अंदर बसी हुई गूढ़ आध्यात्मिकता का लाभ भी प्राप्त किया जा सकेगा और इससे राष्ट्र निर्माण का अभूतपूर्व कार्य भी पूर्ण हो सकेगा। अगर प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये विचार होगा कि वो उस शरीर का हिस्सा है जिसका हिस्सा प्रत्येक दूसरा व्यक्ति है तथा प्रत्येक दूसरे व्यक्ति का सुख–दुःख उसे प्रभावित किए बिना नहीं रह सकेगा इसलिए उसे दूसरों के सुख–दुःख के प्रति संवेदनशील होना चाहिए तो समाज में बँटवारे की गुंजाइश सिर्फ इतनी होगी जितना की शरीर का प्रत्येक अंग अपना अलग–अलग कार्य करता है परंतु प्रत्येक का कार्य होता पूरे भारीर के लिए ही है और उस भारीर से अलग उस किसी भी विशेष अंग का कोई महत्त्व नहीं रह जाता है। अगर जीभ के स्वाद को इसलिए नियंत्रण में रखा जाएगा कि इसमें पेट को परेशानी हो सकती है तो शरीर का संतुल बना रहेगा ठीक वैसे ही समाज का प्रत्येक वर्ग अपने स्वार्थ पर दूसरों के हितों को ध्यान में रखते हुए अगर नियंत्रण रखेगा तो राष्ट्रीय एकता का संतुलन स्थाई रूप से बन जाएगा। इस प्रकार भारत में 2047 तक हमें एक ऐसा विकास करना होगा जो भारत को भौतिक, आध्यात्मिक, मूल्यात्मक और सामाजिक रूप से विकसित देश बना दे।

1. पिट्टी, आदित्य, विकसित भारत 2047, फिंगराप्रिंट पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2025
2. कुशवाह, संचिता, विकसित भारत लक्ष्य 2047, स्वस्तिक पब्लिकेशन्स, 2025
3. पाण्डेय, संदीप कुमार, जैन एकता, रश्मि, विकसित भारत 2047 अपेक्षाएं व चुनौतियां, वान्या पब्लिकेशन्स, 2024
4. डॉ द्विवेदी अजय, दुबे, शिखा, डॉ तोमर, सहदेव सिंह, विकसित भरत, 2047 (इनोवेंशस, चैलेंज़ेज एण्ड पॉलिसी इम्परीटीज़) डी॰ पी॰ एस पब्लिशिंग, हाउस, दिल्ली, 2025
5. पाण्डेय, मनीष कुमार, विकसित भारत 2047, अस्तित्व प्रकाशन, दिल्ली, 2024